सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

जल है तो कल है

प्रेरणा

ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करे बल्कि ध्यान भी लगाए। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं।

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-4 • 31 MARCH TO 06 APRIL 2023 • VOLUME 36 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay Money after the Visa

•IELTS •STUDY ABROAD

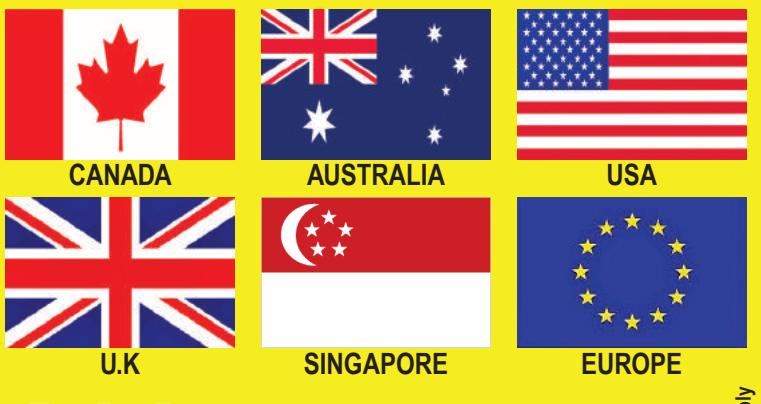

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

*T&C apply

रामनवमी पर बड़ा हादसा : मंदिर की छत धंसी, कई श्रद्धालुओं की मौत

पीएम मोदी ने जताया दुख, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी के मौके पर बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हादसा मंदिर में हुआ जहां राम नवमी के मौके पर यज्ञ का आयोजन हो रहा था, तभी मंदिर के नीचे बनी बावड़ी की छत धंस गई, जिससे 25 लोग नीचे पानी में जा गिरे। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए है।

जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। अब भी कई लोग नीचे फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्कयू ऑपरेशन चलाने में परेशानी हो रही है क्योंकि यहां बावड़ी में नीचे काफी पानी है। ऐसे में पानी निकालने के लिए भी इंतजाम किए गए है। मोटर से पानी निकालने की कोशिश हो रही है। जिलाधिकारी डॉ. टी. इलैयाराजा ने बताया कि हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल की मदद से बचाव अभियान

जारी है और अब तक करीब 20 लोगों को बचाया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन ऐसे सार्वजनिक स्थानों को चिह्नित करेगा, जहां इस तरह के हादसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के संकरी जगह में बने होने के कारण बचाव कार्य में बाधा आई और इस दौरान मंदिर की एक दीवार तोड़ कर पाइप इसके भीतर डाला गया और बावड़ी का पानी मोटर से खींचकर बाहर निकाला गया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंदिर में पुरातन बावड़ी की छत पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी और छत ज्यादा लोगों का बोझ नहीं सहन कर सकी। लोगों ने बताया कि मंदिर पुरातन बावड़ी पर छत डालकर बनाया गया था। हादसे के बाद मंदिर के आस-पास उन चिंतित लोगों की भीड़ जुट गई जिनके परिजन हादसे के वक्त मंदिर में मौजूद थे। पटेल नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष कांतिभाई पटेल ने इस बात पर नाराजगी जताई कि हादसे की सूचना दिए जाने के बाद भी एक घंटे तक मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में स्थित एक मंदिर में बृहस्पतिवार को रामनवमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने की घटना पर दुख जताया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात कर हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''इंदौर में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और ताजा स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार तेजी से बचाव और राहत कार्य चला रही है। सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना।''

इस घटना पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नजर बनाई हुई है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों के इलाज के लिए 50 हजार रुपये दिए जाने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को कृषि में बेमिसाल तबदीली का न्योता

पीएयू प्रामाणित कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी

मानसा, बठिंडा, मुक्तसर साहिब और फाज़िल्का ज़िलों के किसानों को मूँग की दाल की कृषि से बचने की अपील

• जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़

पंजाब के लिए फ़सलीय विविधता को अहम ज़रूरत बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को कपास, बासमती और मूँग की दाल जैसी वैकल्पिक फसलें अपनाकर कृषि में बेमिसाल तबदीली लाने का न्योता दिया। राज्य के किसानों को वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की जरखेज़ ज़मीन पर कई फसलें उगाई जाती थीं, परन्तु धीरे-धीरे किसान धान तक सीमित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसका राज्य की आर्थिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके लिए बिजली और पानी का बहुत अधिक प्रयोग करना पड़ता है, जिससे पंजाब के कई इलाके डार्क ज़ोन में आ चुके हैं। इसके साथ-साथ पराली जलाने और अन्य समस्याएँ भी पैदा होती हैं। भगवंत मान ने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए वैकल्पिक फसलें अपनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए राज्य के

मुख्य सचिव के नेतृत्व अधीन एक समिति बनाई गई है, जो वैकल्पिक फसलों के बारे में सुझाव देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए राज्य सरकार पहली अप्रैल से कपास की फ़सल के लिए नहरी पानी मुहैया करने की गारंटी देने के साथ-साथ पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी (पी.ए.यू.) से प्रमाणित कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इसके साथ-साथ कपास की फ़सल पर बीमा और बासमती पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बासमती पर कीटनाशकों के छिडक़ाव की मात्रा तय करने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए लैबोरेटरियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बासमती की फ़सल कीटनाशक अवशेष सम्बन्धी यूरोपीय मुल्कों के निर्यात मापदण्डों पर खरी उतरे। उन्होंने धान की पी.आर. 126 और ऐसी अन्य किस्मों की कृषि की सिफ़ारिश करते हुए कहा कि पी.ए.यू. द्वारा प्रमाणित किस्मों को प्रोत्साहित करने और पूसा 44 जैसी पकने के लिए अधिक समय और ज़्यादा पानी लेने वाली किस्मों की खेती से किसानों को रोकने के लिए कोशिशें हो रही हैं। भगवंत मान ने यह भी कहा कि मूँग की दाल पर एम.एस.पी. जारी रहेगी, परन्तु हालिया खोजों में पता चला है कि मूँग की दाल की फ़सल पर पैदा होने वाली सफ़ेद मक्खी कपास पर तबदील हो जाती है, जिस कारण मानसा, बठिंडा, मुक्तसर साहिब और फाज़िल्का ज़िलों के किसानों को मूँग की दाल की कृषि न करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि ऐसे खतरों से किसानों को अवगत करवाने के लिए 2500 किसान मित्र और पी.ए.यू. के 100 कृषि विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे।

1 अप्रैल से फ़सल की निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित बनाने के लिए वचनबद्ध : लाल चंद कटारूचक्क

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले आगामी रबी मंडीकरण सीजन (आरएमएस) के दौरान गेहूँ की निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इस सम्बन्धी राज्य की सभी मंडियों में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज यहाँ बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्विघ्न खरीद प्रक्रिया के लिए 29,000 करोड़ रुपए की नकद कर्ज सीमा (सी.सी.एल.) की मंजूरी दी गई है। मंत्री ने आगे कहा कि पहले दिन से ही फ़सल की अदायगियाँ सुनिश्चित बनाई जाएंगी और किसानों की फ़सल का दाना-दाना खरीदा जायेगा। इसके साथ ही गेहूँ की रीसाइक्लिंग को रोकने के लिए खरीद केंद्र से स्टोरेज प्वाइंट तक गेहूँ की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ट्रांसपोर्ट वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने अनिवार्य किए गए हैं।

राम नवमी पर मुख्यमंत्री ने श्री देवी तालाब मंदिर में माथा टेका

• जालंधर ब्रीज.जालंधर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरूवार को श्री राम नवमी के पवित्र अवसर पर पवित्र शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर में माथा टेका और राज्य की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। भगवान राम के जन्म दिवस 'राम नवमी' के शुभ अवसर पर पंजाब के लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र अवसर मानव एकता और आपसी-भाईचारे का प्रतीक होने के साथ-साथ लोगों को भगवान राम (मर्यादा पुरूषोत्तम) द्वारा सिखाए गए नैतिक और आध्यात्मिक नैतिक मूल्य अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने एक खुशहाल और सद्भावना वाले समाज की सृजना करने के लिए हमें आदर्श और सदाचार वाले जीवन का मार्ग दिखाया। भगवंत मान ने लोगों को भगवान राम की शिक्षाओं को असली भावना के साथ अपनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह शिक्षाएं आज के

पदार्थवादी समाज में भी प्रासांगिक हैं और समाज को बुराईयों के जाल से मुक्त करने में मदद कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पवित्र अवसर पर न केवल लोगों में आपसी-भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भावना और आपसी सांझ की भावना को प्रफुल्लित करते हैं, बल्कि असंख्य खुशी और खुशहाली की रहमत का संयोग भी बनते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस पवित्र दिवस को जात-पात, रंग, नसल और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और सद्भावना की भावना से मनाएँ।

पीएम मोदी ने नए संसद भवन का किया दौरा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से की बात

नई दिल्ली. पीएम मोदी गुरुवार (30 मार्च) देर शाम को नए संसद भवन के औचक दौरे पर गए। उन्होंने एक घंटे से अधिक समय बिताया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने साथ ही निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया था। नए भवन की अक्टूबर 2022 तक संसद के शीतकालीन सत्र को पूरा करने की उम्मीद है। नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर होगा।

सस्ता प्लॉट बेचने के दोष अधीन दो काबू

अदालत द्वारा मुलज़िम 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर विजीलैंस के हवाले

• जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम के दौरान पूर्व वन मंत्री पंजाब साधु सिंह धर्मसोत के पुत्र हरप्रीत सिंह को 60 लाख रुपए में प्लॉट खरीदने की साजिश के अंतर्गत उसी दिन केवल 25 लाख रुपए में बेचने के दोष अधीन उक्त हरप्रीत सिंह के अलावा तीन अन्य व्यक्तियों को पहले से ही दर्ज भ्रष्टाचार के एक मुकदमे में बतौर दोषी नामज़द किया है। इस केस में विजीलैंस ब्यूरो द्वारा दो मुलज़िम राजेश कुमार चोपड़ा और राज कुमार नागपाल को गिरफ्तार करने के उपरांत मोहाली की अदालत में पेश करके 6 दिनों का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इस मुकदमे की आगे की पड़ताल जारी है।

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो द्वारा पहले ही मुकदमा नंबर 06 तारीख़ 06-02-2023 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो उड़न दस्ता, पंजाब, मोहाली के थाने में दर्ज है। इस केस की जाँच से पाया गया कि मुलज़िम राज कुमार नागपाल, निवासी सैक्टर 8 पंचकूला, हरियाणा द्वारा प्लॉट नंबर 2023, सैक्टर-88 मोहाली की एल.ओ.आई. गुरमिन्दर सिंह गिल, निवासी कोठी नंबर 1677, फेज़-3बी-2 मोहाली से तारीख़ 27.11.2018 को एक अश्टाम (नंबर एई773271) के द्वारा 60 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि उसी दिन उसी अस्टाम की श्रृंखला में एक अन्य अश्टाम (नंबर एई773272) खरीद करके, मुलज़िम राज कुमार द्वारा यही प्लॉट आगे दोषी साधु सिंह धर्मसोत, पूर्व वन मंत्री पंजाब के पुत्र हरप्रीत सिंह को करीब 35 लाख रुपए में घटाकर केवल 25 लाख रुपए में साजिश के अंतर्गत बेच दिया गया। इस प्लॉट की खरीद और बिक्री के समय मुलज़िम राजेश कुमार चोपड़ा, निवासी सैक्टर 82 जे.एल.पी.एल., मोहाली द्वारा बतौर गवाह दस्तखत किए गए।

रोप-वे प्रोजैक्ट विकास के साथ सैलानियों की सुविधा के लिए भी होगा सहायक : अनमोल गगन मान

जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़ : पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने श्री आनन्दपुर साहिब-नैना देवी और पठानकोट-डलहौज़ी क्षेत्रों में साझे तौर पर रोपवे प्रोजैक्ट विकसित करने के लिए आपसी सहमति पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की सराहना की है। इस प्रोजैक्ट से दोनों राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि रोप-वे प्रोजैक्ट सैलानियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा और इससे स्थानीय आर्थिकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह क्षेत्र के सबसे सुंदर कुछ स्थानों तक आसान पहुँच प्रदान करेगा, जिससे बिना शक बड़ी संख्या में सैलानी आकर्षित होंगे। इस प्रोजैक्ट से दोनों राज्यों के दरमियान संपर्क में सुधार की भी उम्मीद है, जिससे व्यापार और कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दोनों मुख्य मंत्रियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद की कि यह प्रोजैक्ट जल्द ही मुकम्मल हो जायेगा और देश भर के सैलानियों को आकर्षित करेगा।

जी20 : चंडीगढ़ में दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश

वैश्विक कृषि विकास के लिए आम सहमति विकसित करने के महत्व पर डाला प्रकाश

• जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़

भारत कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक 29 से 31 मार्च 2023 तक चंडीगढ़ में चल रही है। इस कार्यक्रम में 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई है। 30 मार्च को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आम सहमति विकसित करने में विश्वास व्यक्त किया। उद्घाटन सत्र के दौरान मंत्री सोम प्रकाश ने चंडीगढ़ में दूसरे एडीएम में शानदार व्यवस्था

के लिए भारतीय प्रेसीडेंसी की सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों का उनकी बहुमूल्य भागीदारी के लिए स्वागत किया और उद्घाटन वीडियो की सराहना की, जिसने खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। मंत्री सोम प्रकाश ने अपने संबोधन में मसौदा विज्ञप्ति पर उपयोगी चर्चाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा "बैठक में चर्चा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर आम सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी, और मुझे विश्वास है कि हम इसे हासिल करेंगे। हमें 'वैश्विक कृषि परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए 'वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर' की भावना से मिलकर काम करने की जरूरत है।"

दूसरे एडीएम के सदस्य देश चार विषयगत क्षेत्रों, अर्थात् खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली, और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण को संबोधित करते हुए विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी समापन टिप्पणीयों में मंत्री सोम प्रकाश ने प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ में एक शानदार अनुभव की कामना की और आशा व्यक्त की कि वे सुखना झील और यादविंद्रा गार्डन, पिंजौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यंजनों के साथ नियोजित यात्राओं और भ्रमण का आनंद लेंगे। चंडीगढ़ में दूसरे एडीएम द्वारा वैश्विक कृषि परिदृश्य की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करने वाली विज्ञप्ति के साथ, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ने पर आम सहमति के लिए नींव रखने की उम्मीद है।

TRAVELING

कर्नाटक में ताड़ के पेड़ से घिरे नीले-नीले समुद्र छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट हैं। यहां के कुछ फेमस बीच हैं जिन्हें देखकर आपको बाली की याद आ जाएगी...

कर्नाटक के इन 4 बीच पर पार्टनर संग घूमने का है अलग मजा, एक बार जरूर करें विजिट

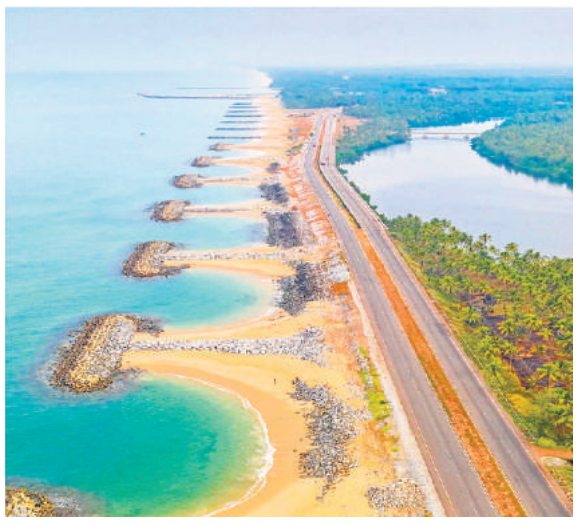

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

भीड़भाड़ से दूर, शांत जगह पर बैठकर नीले पानी को देखना काफी ज्यादा रिलेक्सिंग हो सकता है। अगर घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कर्नाटक के खूबसूरत बीच देखने के लिए जा सकते हैं। यहां के बीच पर शांति में आप सूर्यास्त और सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। यहां कुछ बीच बता रहे हैं जिन्हें देख कर आपको बाली की याद जरूर आएगी।

कुडले बीच

गोकर्ण में कुडले बीच शहर की हलचल से बाहर निकलने और खुद को ट्यून करने के लिए एक अच्छा बीच है। भीड़ से एकांत की तलाश के लिए इस जगह पर जा सकते हैं। कुडले बीच पर आपको रात में बांस की झोपड़ियों में बैठने का आनंद मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये नया एक्सपीरियंस होगा।

कोडी बीच

कुंदापुर से 4 किमी दूर स्थित, कोडी बीच सुवर्णा नदी अरब सागर में मिलती है। इसे कर्नाटक के विदेशी समुद्र तटों में से एक के रूप में जाना जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहां पर फ्रेश समुद्री खाने का आनंद ले सकते हैं। यहां पर लोग सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे का आनंद लेने के लिए नाव की सवारी कर सकते हैं।

देवबाग बीच

देवबाग बीच को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह देखने लायक है। यहां काली नदी अरब सागर से मिलती है। हरे-भरे पहाड़ों से घिरा, और सफेद सीगलों द्वारा दौरा किया गया, देवबाग समुद्र तट पर आप अपनी चिंताओं को एक तरफ रख, सिर्फ नीले पानी को एंजॉय करें।

हूड बीच

हूड बीच उडुपी से लगभग 20 किलोमीटर दूर बेंगरे में स्थित है। यहां पर आप बेहद खूबसूरत सूर्यास्त और सूर्योदय को देख सकते हैं। सर्फिंग के लिए उडुपी में यह सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है।

FASHION+

मलाइका अरोड़ा की बैकलेस ड्रेस ने जाह्नवी कपूर के ग्लैमरस लुक को भी छोड़ दिया पीछे

हंगामा स्टाइल आइकॉन अवॉर्ड फंक्शन में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के बीच जाह्नवी कपूर, मलाइका अरोड़ा के सुपर हॉट बैकलेस ड्रेस ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

मुंबई में हुए स्टाइल आइकॉन अवॉर्ड में बीटाउन की लगभग सारी हसीनाएं मौजूद थी। इस लिस्ट में जाह्नवी कपूर, मलाइका अरोड़ा, कृति सेनन, तमन्ना भाटिया, रश्मिका मंदाना से लेकर अनुष्का शर्मा, मौनी रॉय, शहनाज गिल तक शामिल हैं। स्टाइल आइकॉन अवॉर्ड के लिए इन हसीनाओं का गॉर्जियस लुक देखने को मिला। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी जाह्नवी कपूर और मलाइका अरोड़ा ने। अर्जुन कपूर के साथ अवॉर्ड शो में पहुंची मलाइका अरोड़ा 48 की उम्र में बाकी हसीनाओं को हॉट एंड बोल्ड लुक के मामले में पीछे छोड़ती नजर आईं।

जाह्नवी कपूर का ग्लिटरी लुक : जाह्नवी कपूर अक्सर इवेंट में बेहद गॉर्जियस लुक के साथ पहुंचती हैं। जिसमे वो अपनी स्लिम फिगर जबरदस्त तरीके से फ्लांट करती है। इस बार भी अवॉर्ड शो के लिए जाह्नवी ने डार्क मरून शेड की शिमर वर्क ड्रेस को चुना। जिसकी फुल स्लीव और हाई नेकलाइन स्लिम बॉडी को फ्लांट कर रही थी। तो वहीं कमर पर बनीं कटआउट डिटेलिंग उनके कर्व्स को फ्लांट करने के लिए काफी दिख रही थी।

रिस्की थी थाई हाई स्लिट : रिस्की थाई हाई स्लिट के साथ जान्हवी ने काफी हाइलाइटेड मेकअप किया था। ब्लैक विंग्ड आईलाइनर के साथ ग्लॉसी न्यूड शेड लिपस्टिक और बीमिंग हाईलाइटर खूबसूरती को उभारने के लिए परफेक्ट दिख रहे थे।

मलाइका अरोड़ा की बैकलेस ड्रेस ने लूटी लाइमलाइट : वहीं इस अवॉर्ड फंक्शन में अर्जुन कपूर के साथ पहुंची मलाइका अरोड़ा का सुपर हॉट लुक देखने को मिला। ऑल ब्लैक गाउन में पहुंची मलाइका के इस गाउन में लगभग बेयर बैक डिजाइन थी। जो मलाइका को सिजलिंग हॉट लुक दे रही थी। वहीं बालों की पोनी बनी थी। जिसे सिल्वर गोटे से लपेटा गया था।

पूरी ड्रेस थी हॉट : हाई नेकलाइन और फुल स्लीव के साथ इस ड्रेस पर वेस्ट पर कटआउट डिटेलिंग की गई थी। वहीं बैक पर भी थाई हाई स्लिट बना था। जो इसे पूरी तरह से बोल्ड लुक वाली ड्रेस बना रहा था।

लोहे के बर्तन में कभी ना बनाएं ये फूड्स, पूरे टेस्ट का हो जाएगा कबाड़ा

लोहे के बर्तन में कुछ खाने को पकाने पर सेहत को फायदा मिलता है तो वहीं कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोहे के बर्तन में भूलकर भी नहीं पकाना चाहिए।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

आजकल कई मेटल के बर्तन मार्केट में आने लगे हैं। नॉनस्टिक से लेकर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टील की कोटिंग के नए बर्तन भी मार्केट में मिलने लगे हैं। लेकिन आज भी कुछ खाने ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा लोहे के बर्तनों में बनाने की सलाह दी जाती है। जिससे खाने में आयरन की मात्रा और बढ़ जाए और खाना हेल्दी बने। खासतौर पर हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कड़ाही में बनाना अच्छा माना जाता है। इससे सब्जी का पौष्टिक तत्व बढ़ जाता है। वहीं जब हम स्ट्रीट फूड में चाउमीन खाते हैं तो वो यम्मी सी चाउमीन हमेशा लोहे के बर्तन में बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ फूड ऐसे भी हैं जिन्हें लोहे के बर्तन में बना देने से उनका स्वाद पूरा बिगड़ जाता है।

फिश : फिश को कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। पकाते समय मछली लोहे के बर्तन में चिपक जाती है जिसकी वजह से इसे पकाना मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर इसका हिस्सा जल जाता है। लोहे के बर्तन में मछली को पकाने से उसका स्वाद खराब हो जाता है।

अंडा : अंडे के स्वाद को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लगो इसे लोहे के पैन में बनाना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अंडा पैन से चिपकता है और इसे करछूल से खुरचना पड़ता है। जिससे ऑमलेट में लोहे का स्वाद आने लगता है और पैन भी खराब हो जाता है।

पास्ता : पास्ता काफी डेलिगेट डिश है जिसे काफी सावधानी से बनाने की जरूरत होती है। ओवरकुक पास्ता काफी चिपचिपे से हो जाते हैं और बर्तन से चिपकने लगते हैं। अगर कभी आपका पास्ता ओवरकुक हुआ है तो उसे लोहे के पैन या कड़ाही में बनाने की गलती ना करें। इससे लोहे का पैन भी खराब हो जाता है और पास्ता का स्वाद भी बिगड़ जाता है।

हलवा या स्वीड डिश : अगर आप कभी गलती से हलवे को लोहे की कड़ाही या पैन में बना देती हैं तो इससे हलवे में आयरन की महक और स्वाद आना शुरू हो जाएगी। इसलिए लोहे के बर्तन में हलवा या स्वीट डिश ना बनाने में ही भलाई है।

एसिडिक फूड्स : अगर आप किसी फूड में टमाटर, अमचूर, सिरका, नींबू जैसी खट्टी चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरह के फूड आइटम को लोहे के बर्तनों में बनाने से अवॉइड करने में ही भलाई है। क्योंकि इससे स्वाद बिगड़ जाता है।

बच्चे को लग गई है टीवी की लत, तो ऐसे रखें आंख और कान सुरक्षित

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर PARENTING

ज्यादातर बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और स्कूल खुलने से पहले मिली छुट्टियों का बच्चे घर बैठकर मजा ले रहे हैं। उनकी इस छुट्टियों में मोबाइल और टीवी उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। अगर आपके घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, आपको भी लगता है कि आपके बच्चे को मोबाइल या टीवी की लत लग गई है तो तुरंत ये टिप्स अपनाकर उससे उनकी आंखों और कान को होने वाले नुकसान से बचाएं।

पलके झपकाने की आदत

द न्यू इंग्लैंड जनरल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के स्क्रीन देखते समय उसकी पलके झपकाने की स्पीड आधी हो जाती है। जिसकी वजह से उसे आंखों में ड्राइनेस की समस्या होने लगती है। ऐसे में ड्राई आइज की समस्या से बचने के लिए बच्चों को पलकें झपकाने की आदत डालें।

बड़ी स्क्रीन का करें चुनाव

बच्चा फिल्म या कार्टून देख रहा है तो उसे मोबाइल की जगह टीवी पर देखने के लिए कहें। ज्यादा देर तक छोटी स्क्रीन को देखते रहने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। जबकि स्क्रीन पर फोटो जितनी बड़ी दिखेगी, आंखों पर उतना ही कम प्रेशर पड़ेगा।

रोशनी का रखें ख्याल

पैरेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि जब आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा हो तो उस कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि रोशनी कभी भी स्क्रीन के पीछे से नहीं बल्कि खिड़की से आनी चाहिए। स्क्रीन के पीछे से लाइट आने पर बच्चे की आंखों पर दबाव पड़ता है।

कानों को भी रखें सुरक्षित

अगर आपका बच्चा 3 साल से कम उम्र का है तो उसे हेडफोन यूज करने के लिए न दें। लेकिन आपके मना करने के बावजूद अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो डिवाइस लेवल से 50 पर्सेंट तक आवाज़ कम रखें।

फेफड़ों के लिए भी हेल्दी हैं प्लांट बेस्ड फूड्स, सांस की बीमारी में शाकाहार के फायदे

HEALTH CARE

प्लांट बेस्ड फूड पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यदि प्रदूषण और अन्य कारणों से फेफड़े और श्वसन तंत्र में सामान्य दिक्कत हो रही है, तो आहार में अधिक से अधिक प्लांट बेस्ड फूड को शामिल करें।

• **जलंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

पशुओं के प्रति प्रेम और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए प्लांट-बेस्ड या प्लांट-फॉरवर्ड ईटिंग पैटर्न को लाइफस्टाइल में शामिल किया गया। इसमें केवल फल और सब्जियां ही नहीं, बल्कि प्लांट किंगडम से प्राप्त ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, आयल, साबुत अनाज, फलियां और बीन्स शामिल हैं। प्लांट बेस्ड डाइट या वीगन डाइट को अपनाने वाले लोग मांस या डेयरी उत्पाद नहीं खाते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट या वीगन डाइट शरीर के सभी अंगों को लाभ पहुंचाता है। यहां तक की प्रमुख अंग फेफड़े और स्वसन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है।

पोषक तत्व फेफडों को बनाते हैं स्वस्थ

डॉ. बताते हैं, 'प्लांट बेस्ड फूड फेफड़ों के स्वास्थ्य को कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो फेफड़ों स्वस्थ बनाये रखने में मदद करते हैं। प्लांट-बेस्ड फूड में आमतौर पर पोषक तत्वों से भरपूर संपूर्ण खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज शामिल होते हैं। ये विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं। जो श्वसन स्वास्थ्य सहित समग्र शरीर को लाभ पहुंचाते हैं।

कम करते हैं सूजन : यदि श्वसन प्रणाली में किसी प्रकार की सूजन है, तो इसे कम करने में ये आहार मदद कर सकते हैं। प्लांट-बेस्ड फूड फाइबर से भरपूर होते हैं, जो फेफड़ों के कार्य में सकारात्मक सुधार में मदद करते हैं। फाइबर हेल्दी इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम को बढ़ावा देता है, जो इम्यून सिस्टम और सांस के मार्ग की बीमारियों को दूर करता है। सब्जियां, फल, साबुत अनाज, फलियां, नट, और सीड्स जैसे खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सिडेंट्स और अन्य फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेट्री होते हैं। ये फेफड़ों को प्रदूषण, धूम्रपान और अन्य पर्यावरणीय कारकों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं।

इन खाद्य पदार्थों को आहार में करें शामिल

फ्लैक्ससीड्स, चिया बीज और अखरोट : फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी फैट शामिल करें। फ्लैक्ससीड्स, चिया बीज, अखरोट और एवोकाडो जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ओमेगा -3 फैटी एसिड जैसे हेल्दी फैट फेफड़ों में सूजन को कम करने और श्वसन क्रिया में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। खूब फल और सब्जियां खाएं। इनमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट मौजूद होते हैं।

टोफू और टेम्पेह जैसे हाई प्रोटीन स्रोत : फलियां, नट, बीज, और सोया उत्पाद जैसे टोफू और टेम्पेह पौधे-आधारित प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

जी-20: एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के प्रतिनिधियों को रॉक गार्डन, चंडीगढ़ ने किया मंत्रमुग्ध

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

भारत – जी-20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के प्रतिनिधियों को 29 मार्च, 2023 को एक सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के चमत्कारों का पता लगाने का मौका मिला। उद्यान, जिसे नाथूपुर के नेकचंद सैनी के रॉक गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, एक मूर्तिकला उद्यान है जो पूरी तरह से औद्योगिक और घरेलू कचरे और बेकार वस्तुओं से बनाया गया है। प्रतिनिधि बगीचे की सुंदरता और विशिष्टता से मुग्ध थे।

उनके साथ स्थानीय नृत्य और संगीत की विशेषता वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें क्षेत्र की समृद्ध और विविध पाक विरासत का अनुभव करने का मौका मिला। बाजरा से बने व्यंजन में बाजरा चीज़केक, बाजरा चॉकलेट ब्राउनी, बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा, बाजरा टिक्की और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

मुख्य आकर्षण में से एक प्रतिनिधियों के लिए मेहंदी कला को आजमाने का अवसर था। कई विदेशी महिला प्रतिनिधि इस प्राचीन भारतीय कला रूप से मोहित हो गईं और अपने हाथों पर जटिल डिजाइन प्राप्त करने का आनंद लिया।

प्रतिनिधियों को दिखाई गई फिल्म में रॉक गार्डन के इतिहास और कामकाज को दर्शाया गया। वे नेक चंद और इस परियोजना पर काम करने वाले लोगों के समर्पण से चकित थे।

रॉक गार्डन के बारे में उद्यान के संस्थापक, नेकचंद सैनी, एक सरकारी अधिकारी थे, जिन्होंने 1957 में अपने खाली समय में गुप्त रूप से उद्यान का निर्माण शुरू किया था। आज उद्यान 40 एकड़ (16 हेक्टेयर) के क्षेत्र में फैला हुआ है और रचनात्मकता का एक प्रमाण है।

पीआईबी चंडीगढ़ ने करनाल में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया

• **जालंधर ब्रीज.** ; चंडीगढ़

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), चंडीगढ़ ने आज जिला करनाल में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पीआईबी और जिला और उप-जिला स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना था। मंगलसेन ऑडिटोरियम, करनाल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने पीआईबी चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक राजेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में किया।

अतिरिक्त महानिदेशक (क्षेत्र) पीआईबी चंडीगढ़, राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि सूचना के प्रसार के लिए मीडिया सबसे शक्तिशाली साधन है। खोजी पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, मीडिया को विकास पत्रकारिता पर भी ध्यान देना चाहिए और जमीन से सफल और सकारात्मक कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्टिंग से पहले पत्रकारों के लिए मीडिया नैतिकता और आचार संहिता पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में यह क्षेत्र मीडिया के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक सक्रिय भागीदारी का गवाह बनेगा।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए, चौधरी ने यह भी दोहराया कि पत्रकारों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी को बढ़ाना चाहिए और जनता के बीच विकास के संदेश को प्रसारित करने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने पीआईबी फैक्ट चेक के बारे में भी बात की, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी और अन्य संबद्ध मीडिया इकाइयों के कामकाज के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति देते हुए फर्जी खबरों को नकारने में मदद कर सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया अब सूचना प्रसार के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि, हमें फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से सावधान रहना चाहिए और हमें केवल सत्यापित जानकारी ही साझा करनी चाहिए।

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में जिला करनाल में मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' के आयोजन के लिए पीआईबी चंडीगढ़ के प्रयासों की सराहना की, जिसे उन्होंने मीडिया और सरकार के बीच संवाद के लिए सबसे अच्छा मंच करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया सरकार की आंख और कान के रूप में कार्य करता है और जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और चिंताओं को दूर करने के लिए इस तरह का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया दोधारी तलवार की तरह काम करता है और यह मीडिया पर निर्भर है कि वह सकारात्मक और विकासात्मक कहानियों को जन-जन तक पहुंचाए या नहीं और मीडिया को रचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए खुद का इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रो. डॉ आबिद अली ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही व्यावहारिक सत्र प्रस्तुत किया और कहा कि सोशल मीडिया मुख्यधारा के मीडिया के साथ दर्शकों के एकीकरण के माध्यम से सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रामाणिक जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रो. सत्येंद्र यादव ने ड्रोन संचालन, उपयोग और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों के जीवन के जोखिम को कम करती है, पानी और समय की बचत करती है और फसल के खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान लागत प्रभावी होती है।

डॉ. रश्मि सिंह ने आज के समाज में महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला और महिलाओं के कल्याण की दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं से अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाओं का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। "ये योजनाएं महिलाओं को खुद को बेहतर बनाने के अलावा अन्य अवसर प्रदान करती हैं।"

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, करनाल मनोज कौशिक ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रयास की सराहना की और कहा कि ज्यादातर मीडिया घटनाओं के कवरेज में शामिल होने के विपरीत, आज पीआईबी ने उन्हें इवेंट का स्टार बनने का अवसर दिया है और ऐसा बेहतर समन्वय के लिए क्षेत्र में मीडिया कार्यशालाओं की नियमित रूप से मदद की जानी चाहिए।

वाटिका चंद्रा, फील्ड प्रचार अधिकारी, पीआईबी चंडीगढ़ ने मीडिया और अतिथियों का स्वागत किया और अहमद खान फील्ड प्रचार अधिकारी, सीबीसी चंडीगढ़ ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 70 से अधिक पत्रकारों ने कार्यशाला में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए।

कार्यशाला का आयोजन आम नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में पत्रकारों को जागरूक करने के लिए किया गया था। "वार्तालाप" शीर्षक वाली यह कार्यशाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया आउटरीच रणनीति का हिस्सा है और सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी के साथ पत्रकारों को सशक्त बनाकर जनता और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए संकल्पित है।

तकनीकी सत्रों के बाद इंटरैक्टिव प्रश्न-उत्तर सत्र हुआ। कार्यशाला के बाद हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट निशा सोलंकी द्वारा ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए, और रचनात्मक फ़ीडबैक प्रदान की। पत्रकारों ने कार्यशाला आयोजित करने के लिए पीआईबी को भी धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

जी20 के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक चंडीगढ़ में शुरू हुई

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक (एडीएम) आज यानी 29 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू हुई। यह दिन कृषि बाजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) के रैपिड रिस्पांस फोरम (आरआरएफ) को समर्पित था और इसकी शुरुआत वरिष्ठ आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार अरुण कुमार की स्वागत टिप्पणी से हुई। उन्होंने आरआरएफ के 12वें सत्र में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समय की मांग के अनुसार समय पर साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के बारे में बात की ताकि खाद्यान्न की ऊंची कीमतों की चिंता को दूर किया जा सके।

सत्र का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. अभिलाक्ष लिखी की टिप्पणी से हुआ, जहां उन्होंने उल्लेख किया कि जी20 का मुख्य उद्देश्य एक जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली, और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण के साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण, टिकाऊ कृषि की वर्तमान चुनौती पर आम सहमति बनाना है। डॉ. लिखी ने प्रधानमंत्री मोदी की मिशन लाइफ की कल्पना पर जोर दिया, जिसके माध्यम से हर कोई जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकता है।

आरआरएफ की अध्यक्षता एएमआईएस के अध्यक्ष श्री सेठ मेयर ने की, उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर वर्तमान स्थिति और उसी पर एएमआईएस के योगदान के बारे में बात की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा ने भारत के उदाहरण देते हुए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की आवश्यकता के बारे में बात की जो मानकीकृत और गैर-मालिकाना है। इससे एएमआईएस को उत्पादन अनुमानों, आपूर्ति और खपत पर विश्वसनीय और वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी ताकि देशों को खाद्य बाजारों में झटकों और अस्थिरता का तुरंत जवाब दिया जा सके।

इसके बाद उन्होंने 'खाद्य बाजार की स्थिति और संभावना' पर एएमआईएस के पहले और दूसरे सत्र के वक्ताओं का परिचय दिया, जो क्रमशः वैश्विक खाद्य बाजारों की वर्तमान स्थिति और 2023 के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करने और 2022 में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करने वाली एएमआईएस की स्थिति और 2023 के लिए किसी भी तरह के नए विकास पर आधारित था।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव श्री रितेश चौहान ने तीसरे और चौथे सत्र के लिए वक्ताओं का परिचय दिया। तीसरा सत्र एएमआईएस पहल के भविष्य के विकास की कल्पना पर केन्द्रित था और चौथा सत्र क्षमता निर्माण की जरूरतों और रणनीतियों की पहचान पर आधारित था।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीन कुमार ने पांचवें और छठे सत्र के लिए वक्ताओं का परिचय दिया। पांचवां सत्र क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एशिया की भूमिका पर केन्द्रित था और छठे सत्र की चर्चा आयात करने वाले देशों पर वित्तीय कारकों के प्रभाव पर थी। सैमुअल प्रवीन कुमार ने जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और भोजन की बर्बादी की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में क्षेत्रीय सहयोग और निवेश की आवश्यकता पर बल दिया।

जी-20: सतत जलवायु के लिए जल संरक्षण

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। जी-20 नेतृत्व, देश को ग्लोबल वार्मिंग, भोजन और ऊर्जा की कमी, आतंकवाद, भू-राजनीतिक संघर्ष और डिजिटल अंतर को कम करने समेत विभिन्न आकस्मिक स्थितियों से मुकाबला करने के लिए दुनिया को "भारत के प्रयास तथा वर्तमान स्थिति" (इंडिया स्टोरी) को सामने रखने का अवसर प्रदान करता है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत की जी-20 अध्यक्षता; पिछली 17 अध्यक्षता के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के आधार पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस वर्ष की जी-20 थीम "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"; भारत के "वसुधैव कुटुम्बकम" (विश्व एक परिवार है) के अंतर्निहित दर्शन को पूरी तरह से व्यक्त करती है। यह दर्शन भारत के जी-20 नेतृत्व का मार्गदर्शन करेगा।

पहली जी-20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक एक सकारात्मक परिणाम के साथ संपन्न हुई, जिसमें सभी जी-20 देशों ने भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा प्रस्तावित विषयों पर अपना समर्थन व्यक्त किया। निम्न उर्वरता भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने, समुद्र-तटीय क्षेत्रों में नीली अर्थव्यवस्था के जरिये सतत विकास को बढ़ावा देने, जैव विविधता को बढ़ाने, जंगल की आग और समुद्री कचरे को रोकने, चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने आदि विषयों पर हुई गहन चर्चा ने दूसरे शिखर सम्मेलन में अधिक सकारात्मक व दृष्टिगत विचार-विमर्श के लिए मंच तैयार किया है।

जल संसाधन प्रबंधन के सर्वोत्तम तौर-तरीके

अपनी जी-20 की अध्यक्षता के कार्यकाल के

पंकज कुमार
(सचिव, जल संसाधन विभाग)

दौरान, भारत जलवायु परिवर्तन और जल संकट की चुनौतियों से जुड़े प्रभाव को कम करने के लिए एक एकीकृत, व्यापक और सर्वसम्मति पर आधारित दृष्टिकोण के प्रति आशान्वित है। जल संरक्षण, वास्तव में, भारतीय पहचान और सांस्कृतिक इतिहास का अभिन्न अंग है और वर्तमान समय में यह और अधिक प्रासंगिक हो गया है। पानी की "बचत" करना, केवल जल संरक्षण से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, चाहे समय और स्थान कोई भी हो।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य, 2024 तक 193 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना है। हमारे महत्वाकांक्षी नमामि गंगे मिशन ने नदी के कायाकल्प, प्रदूषण में कमी, पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और नदी बेसिन प्रबंधन के समग्र दृष्टिकोण आदि के सन्दर्भ में मूलभूत बदलाव किये हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इसे प्राकृतिक जगत को पुनर्जीवित करने के लिए विश्व के शीर्ष 10 कायाकल्प कार्यक्रमों (रेस्टोरेशन फ़्लैगशिप) में से एक के रूप में मान्यता दी है।

अति महत्वपूर्ण जल भंडारण अवसंरचना को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए भारत, दुनिया के सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, मांग और आपूर्ति पक्ष से जुड़े कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से भूजल संसाधनों के दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। यह योजना समुदाय के नेतृत्व में, ग्राम पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से वर्तमान में चल रही/नई योजनाओं के संयोजन के जरिये कार्यान्वित की जा रही है।

इन प्रयासों और कई अन्य योजनाओं के साथ, भारत वर्ष 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है। इस परिदृश्य में,

हम दूसरी जी-20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) बैठक की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। यह बैठक जल संरक्षण और सतत तथा समानता आधारित जल संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

हमें उम्मीद है कि जल संसाधन प्रबंधन पर वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों और अभिनव विचारों पर चर्चा करने के लिए बैठक में विभिन्न जी-20 देशों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदी कायाकल्प; जलवायु-अनुकूल अवसंरचना; भूजल प्रबंधन; स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए रणनीति आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए होने वाली चर्चाओं से भाग लेने वाले देशों को एक दूसरे से सीखने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

इतिहास और विरासत गुजरात के पर्याय हैं। गौरवशाली गुजरात में कई प्राचीन शहरों के अवशेषों, महलों, किलों और मकबरे मौजूद हैं, जो राजवंशों के भव्य स्वर्ण युग को दर्शाते हैं। रानी की वाव और अडालज वाव की बावड़ी; प्राचीन जल प्रबंधन प्रथाओं को प्रदर्शित करती हैं तथा ये जल संसाधन संरक्षण के लिए भारत की दीर्घकालिक परंपरा की द्योतक हैं। गुजरात, पुराने और नए पारंपरिक जल ज्ञान तथा जल अवसंरचना निर्माण में उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीकों के मिश्रण के साथ, 20 देशों को एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगा, ताकि प्रत्येक देश का सर्वश्रेष्ठ सामने आ सके और प्रत्येक देश से सीखने का अवसर मिल सके।

शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार : डिप्टी कमिश्नर

लोकसभा क्षेत्र के कुल 1618512 मतदाताओं में 843299 पुरुष, 775173 महिला व 40 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं शामिल

• जालंधर ब्रीज.जालंधर

डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह ने 10 मई को होने वाले लोकसभा क्षेत्र 04 जालंधर के उपचुनाव के संबंध में कहा कि जिला प्रशासन भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिप्टी कमिश्नर ने लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 1618512 मतदाता हैं, जिनमें 843299 पुरुष, 775173 महिला व 40 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के 32668 मतदाता, 100 वर्ष से अधिक आयु के 444 मतदाता, 18 से 19 वर्ष के 23649 युवा मतदाता, 10526 विकलांग मतदाता, 73 एनआरआई मतदाता हैं जबकि 1852 सर्विस मतदाता लिस्ट में शामिल हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में 1972 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 738 शहरी क्षेत्रों में और 1234 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। इन मतदान केंद्रों में 44 मॉडल पोलिंग स्टेशनों के साथ-साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को समर्पित एक विशेष पोलिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। जबकि स्थानीय पिंगलवाड़ा में विकलांगजनों द्वारा विशेष मतदान केन्द्र चलाया जायेगा। जिले में 184 सुपरवाइज़र और 1972 बूथ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

यहां जिला प्रशासनिक परिसर में लोकसभा क्षेत्र 04 जालंधर के उपचुनाव और आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह, जिनके साथ पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल भी मौजूद थे, ने कहा कि 18 से 19 आयु वर्ग जिले में 23649 मतदाता है तथा यदि 18 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी युवा मतदान करने से वंचित रह जाता है तो वह नामांकन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अपना वोट बनवा सकता है।

निगरानी टीमों ने शुरू किया अभियान : डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही उड़न दस्तों ने अपना काम शुरू कर दिया है। 13 अप्रैल को नामांकन शुरू होने के साथ ही व्यय एवं अन्य निगरान टीमों द्वारा भी अपना काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों का कुल चुनावी खर्च 95 लाख रुपये तय किया है। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल ऐप के अलावा हेल्पलाइन 1950 और शिकायत निवारण सैल स्थापित किया गया है।

चुनाव प्रक्रिया का विवरण : डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी, जो 20 अप्रैल तक चलेगी। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 अप्रैल को नामांकन वापस लिये जा सकेंगे। 10 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी।

इस बीच, पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने कहा कि पुलिस प्रशासन लोकसभा क्षेत्र जालंधर के शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

डीसी और पुलिस कमिश्नर ने सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों का लिया जायज़ा

जिला प्रशासन ने 10 मई को होने जा रहे लोक सभा क्षेत्र 04 जालंधर के उपचुनाव को निर्विघ्न, सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए तैयारी कर ली गई है, जिस संबंधी डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह और पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने आज सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बैठक करते हुए जिले में चल रहे चुनाव की तैयारियों का जायज़ा लिया। यहां जिला प्रशासनिक परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर व पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को देखते हुए प्रशासन ने जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर नोडल टीमों का गठन किया है ताकि इस पूरी कवायद को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों मेजर अमित महाजन, वरिंदरपाल सिंह बाजवा और जसबीर सिंह व एसपी (मुख्यालय) जालंधर ग्रामीण मनजीत कौर की उपस्थिति में उन्होंने ए.आर.ओ और अपने पुलिस समकक्षों से कहा कि वे अपनी मैपिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करें ताकि वहां आवश्यक बल तैनात करने के लिए एक विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की जा सके।

तरुण चुघ का भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश राठौर के निवास पर किया स्वागत

• जालंधर ब्रीज.जालंधर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का गुरूवार को जालंधर आगमन पर जालंधर शहर के पूर्व मेयर एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश राठौर ने अपने निवास स्थान पहुंचने पर उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया उनके साथ मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व निकाय मंत्री तीक्ष्ण सूद, राजिंदर मोहन सिंह छीना, पूर्व जिलाध्यक्ष रमन पब्बी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रांत शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सनी शर्मा, अमित गिल, चंद्रशेखर, जिला उपाध्यक्ष मनीष विज, दविंदर भारद्वाज, जिला सचिव अमित भाटिया, अश्विनी अटवाल, यजीत हुरिया, नरेश दीवान, विश्व महेंद्रु, मंडल अध्यक्ष मनीष बल, प्रमोद कश्यप ,विकास शर्मा, गुरमीत सिंह, राजन शर्मा, उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश राठौर ने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ के साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में किए जा रहे आगामी कार्यक्रम और रणनीति के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने 10 मई को होने वाले जालंधर लोक सभा के उप चुनावों को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति के बारे में समीक्षा की और पार्टी द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी लेकर अपने सुझाव दिए।

विधायक ने एक महीने की तनख्वाह किसानों की नुकसानी फसल के मुआवजे में देने का किया एलान

विधायक हरदीप मुंडिया ने साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया, किसानों की पीड़ा की घड़ी में किसानों के साथ मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान और सरकार : हरदीप सिंह मुंडियां

• जालंधर ब्रीज.लुधियाना

विधानसभा क्षेत्र साहनेवाल के विधायक हरदीप सिंह मुंडिया ने आज किसानों को राहत देने के लिए अपनी एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है, पंजाब में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें खराब हो रही है, जिसके चलते साहनेवाल से आम आदमी पार्टी के विधायक हरदीप सिंह मुंडिया ने आज गांवों में खराब हुई फसलों का जायजा लिया और अपनी एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में डालने की अपील का ऐलान किया, इस अवसर पर उन्होंने कहा के किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन इस समय सरकार और विधायक किसानों के साथ खड़े हैं।

इस बीच गांवों में किसानों ने 50 से 70 फीसदी फसल खराब होने की आशंका जताई गई है और किसानों का कहना है कि अब तक 50 से 70 फीसदी गेहूं की फसल खराब हो चुकी है और अगर कल या आने वाले दिनों में फिर बारिश हुई तो यह नुकसान जारी रहेगा और किसानों ने कहा के 80 प्रतिशत से अधिक फसलों का नुकसान हो जाएगा।

विधायक हरदीप सिंह मुड़ियां ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि किसानों की खराब हुई फसलों की तत्काल जांच कराकर उन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घोषित राहत राशि दी जाए, साहनेवाल के विधायक ने कहा कि किसानों को इस समय मेरे वेतन लेने से ज्यादा मदद की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपना मार्च माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की।

चंडीगढ़ में 'जनपरिचय' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

• जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़

'जनपरिचय' की कार्यप्रणाली से सभी को परिचित कराने के उद्देश्य से एनआईसी पंजाब ने शासन सुधार विभाग (डीजीआर) पंजाब और एनआईसी दिल्ली 'जनपरिचय' टीम के सहयोग से एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। निदेशक डीजीआर गिरीश दयालन, उप महानिदेशक एनआईसी, पंजाब विवेक वर्मा, एसआईओ एनआईसी हरियाणा दीपक बंसल और एसआईओ एनआईसी चंडीगढ़ यूटी रमेश गुप्ता ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ कार्यशाला में भाग लिया। 'जनपरिचय' एक सिंगल साईन ऑन प्लेटफॉर्म है, जो सभी ऐप्लीकेशनों (ऐप्स) के लिए एक डिजिटल पहचान के तौर पर काम करता है। यह कार्यशाला करवाने का मकसद हरेक को 'जनपरिचय' की कार्यकुशलताओं और नागरिक केंद्रित सेवाओं में इसकी भूमिका से अवगत करवाना था।

यह प्रणाली प्रामाणिकता और पहचान प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नागरिकों (जी2सी) को निर्विघ्न सेवाओं देने में सहायता प्रदान करती है। इसका प्रस्ताव मीआईटी द्वारा दिया गया था और एन.आई.सी., सी-डेक और एनईजीडी को ''मेरी पहचान'' के अंतर्गत नेशनल सिंगल साईन ऑन (एन.एस.एस.ओ.) प्लेटफॉर्म बनाने का ज़िम्मा सौंपा गया था। 'जनपरिचय' का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुँचने के लिए बार-बार अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता को समाप्त करके नागरिकों को सुविधा सुनिश्चित करना था।

'आप' की टैरिफ नीति पंजाब की इंडस्ट्री को एक और झटका : जयवीर शेरगिल

पंजाब को इंडस्ट्री मुक्त करने के मिशन पर काम कर रही आप : भाजपा

• जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़

पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मीडियम एवं लार्ज इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के बिजली के टैरिफ को 5 रुपये से 5.50 रुपये करने संबन्धी लिया गया विनाशकारी फैसला, पहले से संघर्ष कर रही पंजाब की इंडस्ट्री का खात्मा करने के समान है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने इस इंडस्ट्री विरोधी फैसले पर गहरा दुख प्रकट करते हुए, कहा कि पीएसपीसीएल द्वारा जारी किया गया इंडस्ट्री विरोधी सर्कुलर मीडियम एवं लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिटों को हर साल 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 5 सालों के लिए 5.50 रुपए प्रति किलो वाट एंपियर आवर (केवीएएच) मुहैया करवाने का जिक्र करता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की खबरों के मुताबिक वास्तव में 60 पैसे प्रति यूनिट की कुल बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक सच्चाई यह भी है कि बिजली

के बिलों पर 20 प्रतिशत टैक्स भी लगाया जाता है, जो इंडस्ट्री पर 2000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भारी भरकम बोझ डाल देगा।

शेरगिल ने कहा कि पीएसपीसीएल द्वारा यह इंडस्ट्री विरोधी फैसला भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के निर्देशों पर लिया गया है, क्योंकि राज्य का खजाना खाली है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख उद्योगपतियों, खासकर लुधियाना के उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान उन्हें हैरानीजनक सच्चाई के बारे में पता चला कि पंजाब इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी-2022 के तहत नए निवेशकों को दिए गए फायदे से पंजाब के मौजूदा इंडस्ट्री को बाहर रखा गया है। प्रमुख उद्योगपतियों ने उन्हें बताया कि राज्य में आने वाले नए उद्योगों से 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली लिए जाएंगे और उन्हें एक्साइज ड्यूटी में भी 13 प्रतिशत की राहत दी गई है, जिन फायदों से मौजूदा उद्योगों को बाहर रखा गया है। उन्होंने सवाल किया कि इन हालातों में मौजूदा इंडस्ट्री कैसे राज्य में चल सकती है।

शेरगिल ने कहा कि इस फैसले ने पंजाब की इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है। उन्होंने इस फैसले की जोरदार निंदा करते हुए, कहा कि एक उद्योगपति के मुताबिक मौजूदा सरकार वास्तव में इंडस्ट्री से धोखा कर रही है, जो 5 रुपये (अब 5.50 रुपये) प्रति यूनिट चार्ज करने की बात तो कर रही है, लेकिन वास्तव में यदि फिक्स्ड चार्जेस को भी कंजम्पशन चार्जेस के साथ जोड़ दिया जाए, तो इंडस्ट्री लगभग 7 रुपये से 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली अदा कर रही है।

आईपीएल 2023 पर छाया कोरोना का साया

करेंगे नियमों का पालन : बीसीसीआई

मुंबई. आईपीएल के 16वें सीजन के साथ ही कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ सप्ताहों का आंकड़ा देखें तो कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे परेशानी बढ़नी है। कई राज्यों में 30 प्रतिशत कोविड के मामले सामने आए हैं।गौरतलब है की कोरोना वायरस का पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है। एक तरह जहां फैंस आईपीएल को लेकर बेहद उत्साहित है, वहीं टीमें भी आपस में भिड़ने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है जिससे परेशानी खड़ी हो गई है।

बीसीआईसीआई के कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। बीसीआईसीआई स्टेडियम के अंदर भीड़ को संभालने के लिए पूरी तैयारी में है। इसे लेकर बीसीआईसीआई सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बीसीआईसीआई ने एहतियात के तौर पर सभी टीमों के खिलाड़ियों, कोच, स्टाफ, स्टेडियम स्टाफ आदि को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

बीमा, आयुष्मान, सीजीएचएस के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल पर अत्यधिक जेब खर्च : सांसद अरोड़ा

केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं...

• जालंधर ब्रीज.लुधियाना

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर एक प्रश्न के उत्तर में हाल ही में राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19 के अनुसार, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर (कुल स्वास्थ्य व्यय) के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (ओओपीई) व्यय 48.2% है। वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए देश में स्वास्थ्य पर ओओपीई प्रतिशत क्रमशः 60.6%, 58.7%, 48.8% और 48.2% है और इसलिए कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में ओओपीई में गिरावट की प्रवृत्ति है। अरोड़ा के अनुसार यदि हम बीमा प्रीमियम पर खर्च की गई राशि और स्वास्थ्य पर बेहिसाब खर्च की गई राशि को जोड़ दें तो यह 18% के विश्व औसत की तुलना में लगभग 60% होगी। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह यूपी में 70% है जो देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।

वर्ष 2018-19 के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार राज्य-वार ओओपीई निम्नानुसार है: असम (3228 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश (16326 करोड़ रुपये), बिहार (9731 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (3407 करोड़ रुपये), गुजरात (10922 करोड़ रुपये), हरियाणा (6359 करोड़ रुपये), जम्मू और कश्मीर (1772 करोड़ रुपये), झारखंड (7086 करोड़ रुपये), कर्नाटक (10723 करोड़ रूपए), केरल (23702 करोड़ रूपए), मध्य प्रदेश (11550 करोड़ रूपए.), महाराष्ट्र (32251 करोड़ रूपए), ओडिशा (7873 करोड़ रूपए), पंजाब (9196 रूपए), राजस्थान (13438 करोड़ रूपए), तमिलनाडु (14509 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (55829 करोड़ रुपये), उत्तराखंड (1338 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (31115 करोड़ रुपये), तेलंगाना (7332 करोड़ रुपये) और हिमाचल प्रदेश (2226 करोड़ रूपए)।

केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब लुधियाना से 'आप' सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे गए सवाल का दिया। अरोड़ा ने स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने और जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा था; और स्वास्थ्य देखभाल के लिए किए गए जेब खर्च का राज्य/यूनियन टेरिटरी-वार विवरण माँगा था।

अरोड़ा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि वह मंत्री के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उपलब्ध कराया गया आवश्यक डेटा अपडेट नहीं है। उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्री को वर्तमान परिदृश्य में चीजों का विश्लेषण करने के लिए नवीनतम और अपडेटेड डेटा प्रदान करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि 2018-19 के बाद कई बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि आज की आईटी सक्षम दुनिया में दिया गया डेटा इतना पुराना क्यों है। अरोड़ा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) के लिए बजट आवंटन 2017-18 में 47,353 करोड़ रुपये से 82% बढ़कर 2023-24 में 86,175 करोड़ रुपये हो गया है। डीओएचएफडब्ल्यू स्वास्थ्य बजट में आवंटन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। अरोड़ा के अनुसार 2023-24 की यह राशि सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.98% है जबकि विश्व औसत लगभग 7% है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) को 10 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में चौबीसों घंटे मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों और दूर स्थित लोगों के लिए। कार्यक्रम में उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल है। अरोड़ा ने केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इंप्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट (अमृत) फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं।

हेल्थकेयर पर आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (ओओपीई) एक व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य सेवा या सामान प्राप्त करने के समय किए गए भुगतान हैं। ओओपीई आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (क्लिनिक/अस्पताल/फार्मेसी/प्रयोगशाला आदि) के पास सरकारी स्वास्थ्य सुविधा या गैर-लाभकारी संगठन द्वारा संचालित सुविधा के माध्यम से 'मुफ्त' प्रदान नहीं किया जाता है या यदि यह व्यक्ति सरकारी/निजी स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किया गया है।

हवलदार से सहायक सब इंस्पेक्टर प्रमोशन

• प्रभजीत सिंह पीसी ब्रांच कमिश्नरेट जालंधर को हवलदार से सहायक सब-इंस्पेक्टर के तौर पर प्रमोशन होने पर स्टार लगाते कमिश्नर पुलिस जालंधर कुलदीप चाहल व रीडर अमनजीत सिंह।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.